

न्यूज टुडे

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) ने "प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, 2025" जारी की

इस रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया है कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विभाजन को गहरा करने की बजाय समावेशी विकास को बढ़ावा दे।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ AI की क्षमता: वैश्विक स्तर पर 2033 तक AI का बाजार मूल्य 4.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है।
- ▶ नौकरियों पर प्रभाव: AI दुनिया भर में 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ ऑटोमेशन और नौकरियों के खत्म होने से संबंधित चिंताएं भी उत्पन्न होंगी।
- ▶ राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट स्तर पर बाजार का प्रभुत्व:
 - ⊕ वैश्विक कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास व्यय का 40% केवल 100 कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनमें अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की हैं।
 - ⊕ वैश्विक AI निजी निवेश में लगभग 70% निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है।

समावेशी AI हेतु आगे की राह

- ▶ विकासशील देशों में AI को अपनाने को बढ़ावा देना: स्थानीय रूप से उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए AI समाधानों को विकसित करना चाहिए। साथ ही, इस संबंध में कौशल के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को कम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
- ▶ कर्मचारी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना: AI को प्रभावी ढंग से समेकित करने के लिए कार्यप्रवाह और कार्यों को पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- ▶ सरकार की भूमिका: अवसंरचना, डेटा और कौशल इन तीन प्रमुख आयामों पर राष्ट्रीय AI क्षमताओं का मूल्यांकन करना चाहिए।

इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष

- ▶ रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स (UNCTAD): वर्ष 2024 में भारत 36वें स्थान पर था।
- ▶ विशाल प्रतिभा: 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 13 मिलियन GitHub (ओपन-सोर्स परियोजनाओं के लिए प्लेटफॉर्म) डेवलपर्स हैं।
- ▶ सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें: समावेशी AI इकोसिस्टम के लिए इंडिया AI मिशन (2024) शुरू किया गया है तथा अन्य पहलें आरंभ की गई हैं।
- ▶ केस स्टडी: टाटा स्टील ने विविध उत्पादन प्रक्रियाओं में लगभग 250 मशीन लर्निंग सिस्टम्स को अपनाया है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष हुए

सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 वर्ष पूरे हुए।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में

- ▶ इसे गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण (अर्थात मुद्रा/MUDRA ऋण) प्रदान करने के लिए 2015 में प्रारंभ किया गया था।
- ▶ PMMY यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) द्वारा 20 लाख रुपये तक का जमानत-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाए।
 - ⊕ MLIs में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल हैं।
- ▶ ऋण के प्रकार
 - ⊕ शिशु: 50,000 रुपये तक का ऋण;
 - ⊕ किशोर: 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण;
 - ⊕ तरुण: 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच ऋण; तथा
 - ⊕ तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण।

PMMY की उपलब्धियां

- ▶ उद्यमिता में क्रांति: मुद्रा ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी है। PMMY ने 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं।
- ▶ MSMEs वित्त-पोषण: MSMEs को ऋण वित्त वर्ष 2014 में 8.51 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 27.25 लाख करोड़ रुपये हो गया था तथा वित्त वर्ष 2025 में 30 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर सकता है।
- ▶ महिला सशक्तीकरण: सभी मुद्रा लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। यह दर देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- ▶ वित्तीय समावेशन: 50% मुद्रा खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के हैं। इसके अलावा, 11% मुद्रा ऋण धारक अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया

नए वर्गीकरण में, CPCB ने कुल 419 क्षेत्रों को रेड (125), ऑरेंज (137), ग्रीन (94), व्हाइट (54) और ब्लू (9) श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

➤ CPCB ने जल, वायु और खतरनाक अपशिष्ट प्रदूषण के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को समान भारांश देते हुए प्रदूषण सूचकांक पर आधारित एक संशोधित पद्धति का पालन किया है। प्रदूषण सूचकांक को 2016 में उद्योगों के वर्गीकरण के लिए मानदंडों को सुसंगत बनाने हेतु तैयार किया गया था।

नए वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं

➤ ब्लू श्रेणी: इसमें घरेलू/ सामुदायिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को शामिल किया गया है।

⊕ आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं वे सुविधाएं हैं- जो घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने, कम करने एवं निपटाने के लिए जरूरी होती हैं।

➤ संपीडित बायोगैस संयंत्रों (CBG) का वर्गीकरण: जो CBG प्लांट्स नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, कृषि-अवशेष, ऊर्जा फसलें/ घास/ खरपतवार जैसे विविध फीडस्टॉक पर आधारित हैं तथा जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना है, उन्हें ब्लू श्रेणी के तहत रखा जाएगा।

⊕ औद्योगिक या प्रक्रिया अपशिष्ट पर आधारित CBG प्लांट्स रेड श्रेणी में बने रहेंगे।

➤ प्रोत्साहन: पर्यावरणीय प्रबंधन के नियमों का सफल पालन करने वाले उद्योगों को परमिट की अवधि बढ़ाकर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उद्योगों के वर्गीकरण के मापदंड और उदाहरण:

उद्योग	उदाहरण
रेड (PI > 80)	सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स विनिर्माण, डिस्टिलरी (शराब निर्माण इकाइयां) आदि।
ऑरेंज (55 ≤ PI < 80)	ईट-भट्टे, आई सेल बैटरी निर्माण, कोल वॉशरी आदि।
ग्रीन (25 ≤ PI < 55)	कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर (CD/DVD) का विनिर्माण, शीतलन संयंत्र आदि।
व्हाइट (PI < 25)	एयर कूलर की असेंबली, कार्डबोर्ड विनिर्माण, मेडिकल ऑक्सीजन आदि।
ब्लू (CPCB के नए फार्मुले पर आधारित)	नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (सैनिटरी लैंडफिल/ एकीकृत सैनिटरी लैंडफिल, आदि) सीवेज उपचार संयंत्र, आदि।

डायर वुल्स (Direwolves) का पहला सफल डी-एक्सटिंक्शन किया गया

कोलोसल बायोसाइंसेज नामक कंपनी ने दो प्राचीन डायर वुल्फ DNA नमूनों के आधार पर जीन-एडिटिंग और क्लोनिंग की तकनीक से तीन पिल्लों को जन्म देकर इस विलुप्त प्रजाति को दोबारा जीवित किया है।

➤ पारंपरिक क्लोनिंग की बजाय, वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक कम आक्रामक विधि अपनाई, जिसमें ग्रे वुल्फ से एंडोथेलियल प्रोजेनेटर कोशिकाएं (EPC) ली गईं। ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं।

➤ इन कोशिकाओं को जीन एडिटिंग की मदद से डायर वुल्फ के DNA से मेल खाने वाला बनाया गया। इससे डायर वुल्फ का पहला सफल डी-एक्सटिंक्शन संभव हुआ। ध्यातव्य है कि डायर वुल्फ लगभग 10,000-13,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे।

⊕ कोलोसल बायोसाइंसेज अब विलुप्त पिंक पिजन के डी-एक्सटिंक्शन पर भी काम कर रही है। इसके लिए पिंक पिजन के निषेचित अंडाणु में से प्राइमर्डियल जर्म सेल्स (PGCs) निकाले जा रहे हैं। पिंक पिजन मॉरीशस का स्थानिक जीव था।

◆ PGCs वे प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, जो आगे चलकर शुक्राणु और अंडाणु के रूप में विकसित होती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक और एपिजेनेटिक सूचना पहुंचाने का काम करती हैं।

क्लोनिंग क्या है?

➤ क्लोनिंग का अर्थ है किसी जीव की समान प्रति तैयार करना। क्लोनिंग के 2 प्रकार हैं:

⊕ रीप्रोडक्टिव क्लोनिंग: आनुवंशिक रूप से समान जीवों का जानबूझकर क्लोन तैयार करना। उदाहरण के लिए- इस विधि से तैयार पहली क्लोन डॉली नामक भेड़ (1996) थी।

⊕ थेराप्यूटिक क्लोनिंग (भ्रूण क्लोनिंग): इसमें अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भ्रूण की क्लोनिंग की जाती है।

➤ प्रमुख तकनीकें: सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर (SCNT), एम्ब्रियो स्प्लिटिंग आदि।

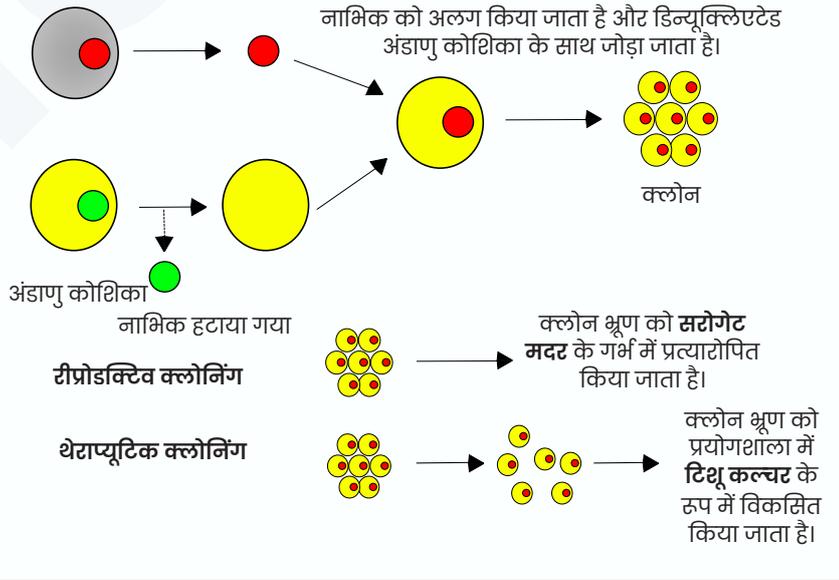
क्लोनिंग से जुड़े नैतिक मुद्दे

➤ जीवों का वस्तुकरण: सहमति के सिद्धांत के बिना जीवों का मानव उपयोग के लिए वस्तु की तरह इस्तेमाल करना।

➤ जैव नैतिकता का उल्लंघन: क्लोनिंग को प्रजनन की प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए- 'वांछनीय' विशेषताओं वाले डिज़ाइनर बेबीज विकसित करना।

➤ कांटीन एथिक्स: स्वयं में अंत और "दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए" के सिद्धांत क्लोनिंग को अनैतिक मानते हैं।

सोमैटिक बॉडी सेल्स जिनमें इच्छित जीन होते हैं



सरकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लवणीय जलीय कृषि केंद्रों की स्थापना पर जोर दे रही है

लवणीय जलीय कृषि (Saline Aquaculture) के बारे में

- अर्थ: इसके तहत अंतर्देशीय लवणीय जलीय कृषि के लिए लवणता प्रभावित भूमि (जो प्रायः पारंपरिक कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है) का उपयोग किया जाता है।
- जलीय कृषि: इसमें जलीय सजीवों जैसे मछली, घोंघे, क्रस्टेशियंस आदि का पालन किया जाता है और जलीय पादपों की खेती की जाती है, ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।
- महत्त्व: जलीय कृषि के लिए लवणीय भूमि संसाधनों की क्षमता का उपयोग करके रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे; जलीय कृषि संबंधी उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा आदि।
- भारत में संभावनाएं:
 - उपर्युक्त 4 राज्यों के 58,000 हेक्टेयर चिन्हित लवणीय क्षेत्रों में से केवल 2,608 हेक्टेयर का ही वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।
 - भारत विश्व स्तर पर संवर्धित झीलों का दुसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही, समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में 65% हिस्सेदारी अकेले झीलों की है, जिसे लवणीय जल-कृषि के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है।

किसानों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियां

नीतिगत चुनौतियां

- अपर्याप्त सब्सिडी
- भूमि की उच्च पट्टा दरें
- यूनिट आकार पर 2 हेक्टेयर की सीमा

इनपुट संबंधी चुनौतियां

- उच्च स्थापना लागत
- लवणता स्तर में उतार-चढ़ाव
- स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज की कमी

आउटपुट संबंधी चुनौतियां

- विपणन संबंधी उचित अवसंरचना की कमी
- उत्पादों के लिए बाजार में कम कीमत

लवणीय जलीय कृषि की क्षमता का उपयोग करने हेतु किए जाने वाले उपाय

- नीतिगत सुधार: क्षेत्र संबंधी सीमा को 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर किया जाना चाहिए। साथ ही, उत्तर भारतीय राज्यों में लवणीय जलीय कृषि के संधारणीय विकास के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का भी गठन किया जाना चाहिए।
- बेहतर विपणन माध्यम: सिरसा में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने की सिफारिश की गई है, ताकि विपणन माध्यमों को बेहतर किए जा सके।
- तकनीकी ज्ञान का प्रसार: राज्यों द्वारा लवणीय जलीय कृषि के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने तथा आउटरीच आधारित अनुसंधान करने हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का उपयोग किया जाना चाहिए।

अन्य सुर्खियां



विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

गृह मंत्रालय के अनुसार, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी व्यक्ति को कोई भी विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

- अंशदान प्राप्त करने की वैधता अवधि 3 वर्ष होगी तथा उक्त अंशदान का उपयोग करने की वैधता अवधि 4 वर्ष होगी।

FCRA, 2010 के बारे में

- उद्देश्य: विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु विदेशी अंशदान को प्रतिबंधित करना।
- इसे FCRA, 1976 की जगह लागू किया गया है।
- 2020 में किए गए संशोधन:
 - एक NGO से किसी दूसरे NGO में धन के अंतरण पर रोक लगाई गई;
 - विदेशी धन के माध्यम से होने वाले NGO के प्रशासनिक खर्चों के लिए किए जाने वाले व्यय को 50% से कम कर 20% कर दिया है। (अर्थात् अब कुल प्राप्त विदेशी धन के 20% भाग को ही प्रशासनिक खर्चों के लिए व्यय किया जा सकता है।)
- विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर प्रतिबंध: चुनावी उम्मीदवार, विधि निर्माता, राजनीतिक दल, लोक सेवक, न्यायाधीश आदि।



प्रोजेक्ट वर्षा

प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत INS वर्षा 2026 तक बन कर तैयार हो जाएगा।

प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में

- यह एक नौसैनिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत की जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना है।
- उद्देश्य: 12 से अधिक परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBNs) के बेड़े को रखने के लिए एक सुरक्षित भूमिगत बेस विकसित करना।
- स्थान: आंध्र प्रदेश का तटीय गांव रामबिल्ली।
- पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए कर्नाटक के करवार बेस को प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत विकसित किया गया है, जो प्रोजेक्ट वर्षा के समान है। प्रोजेक्ट वर्षा पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए है।



वोलैटिलिटी इंडेक्स (India VIX)

हाल ही में, वोलैटिलिटी इंडेक्स (India VIX) ने अब तक का सबसे अधिक एकदिवसीय उछाल दर्ज किया है।

इंडिया VIX के बारे में

- यह बाजार में अस्थिरता (Market volatility) की एक माप है। इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा निफ्टी ऑप्शंस के डेटा का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
- बीटा: समय बाजार के संबंध में किसी स्टॉक की अस्थिरता की माप है।
- उच्च VIX मान पूर्वानुमानित अस्थिरता और अनिश्चितता में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि निम्न VIX मान स्थिर बाजार को दर्शाता है।



राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने 'गांवों में गरीब और निराश्रित लोगों पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के प्रभाव' पर रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बजट बढ़ाने और कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन की सिफारिश की गई है।

NSAP के बारे में

- शुरुआत: इसे 1995 में शुरू किया गया था।
- प्रकार: यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है।
- उद्देश्य: वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों तथा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों के कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु होने पर ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- इसमें पांच योजनाएं शामिल हैं:
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना;
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना;
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना;
 - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना; तथा
 - अन्नपूर्णा योजना।



ग्राफीन

IIT खड़गपुर ने तेल-जल पृथक्करण के लिए ऊर्जा-दक्ष ग्राफीन-आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी तेल रिसाव के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

ग्राफीन के बारे में

- ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है।
- इसमें कार्बन परमाणुओं की एकल परत (मोनोलेयर) होती है। ये परमाणु मधुमक्खी के षट्कोणीय छत्ते जैसी जाली में कसकर बंधे होते हैं।
- गुण: ग्राफीन स्टील से लगभग 200 गुना अधिक मजबूत, हल्का और पारदर्शी होता है।
 - ⊕ इसमें उच्च तन्यता, उच्च तापीय चालकता, लचीलापन आदि गुण होते हैं।
- उपयोग: इलेक्ट्रॉनिक्स (जैसे माइक्रोचिप का निर्माण), ऊर्जा भंडारण (जैसे, बैटरी), जैव चिकित्सा क्षेत्र आदि में।



ऑर्गन-ऑन-चिप

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने भारत में निर्मित ऑर्गन-ऑन-चिप (OOC) विकसित की है। यह चिप द्रव और दवा की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करने में मददगार है। भारत इसका आयात करता है।

ऑर्गन-ऑन-चिप के बारे में

- यह एक छोटा व जैव-इंजीनियरिंग उपकरण है, जो लचीले पॉलिमर से बना है। यह सूक्ष्म स्तर पर मानव अंग की संरचना और कार्य की नकल करने में सक्षम है।
- इसमें अलग-अलग अंगों के ऑन-चिप मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे: लंग्स-ऑन-चिप, लिवर-ऑन-चिप आदि।
- इस चिप में छोटी-छोटी नलिकाएं होती हैं, जिनमें जीवित मानव कोशिकाएं होती हैं और वे आपस में क्रिया करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे शरीर में असली ऊतक करते हैं।
- इनमें रक्त जैसे तरल या दवाएं प्रवाहित करके यह देखा जाता है कि उनका कोशिकाओं पर क्या असर होता है।



स्मॉल हाइव बीटल (SHB)

स्मॉल हाइव बीटल (एथिनाटुमिडा) को भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा गया। यह एक विदेशी या गैर-स्थानिक बीटल है।

स्मॉल हाइव बीटल के बारे में

- मूल स्थान: उप-सहारा अफ्रीका।
 - ⊕ अफ्रीका में यह कम नुकसान करता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही मचाता है।
- विशेषताएं: अंडाकार आकार, लाल-भूरा रंग और लंबाई 5 से 7 मिमी तक होती है। इसका जीवनचक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यस्क के चरणों से गुजरता है।
- नुकसान: स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में दरारों और सुराखों से प्रवेश करती हैं और अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा संग्रहीत शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा जाते हैं, और छत्तों में मल त्यागते हैं। इससे शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।



गैस हाइड्रेट्स

चीन गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए विश्व का पहला स्थायी अंडरसी रिसर्च स्टेशन बना रहा है। गैस हाइड्रेट्स एक संभावित ऊर्जा स्रोत है, जो फारस की खाड़ी के तेल भंडार से भी बड़ा हो सकता है।

गैस हाइड्रेट्स के बारे में

- गैस हाइड्रेट्स जल और गैस से बने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है।
- इन्हें अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इन्हें निकालने के लिए उन्नत और गैर-पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है।
- यह समुद्र नितल के ठीक नीचे कई सौ मीटर मोटी परत में मौजूद है तथा आर्कटिक में पर्माफ्रॉस्ट में भी पाया जाता है।
- भारत में: यह अंडमान द्वीप समूह के आसपास और कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में काफी मात्रा में मौजूद है।

सुर्खियों में रहे स्थल



पुर्तगाल (राजधानी: लिस्बन)

भारत के राष्ट्रपति पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

पुर्तगाल के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति:
 - ⊕ पुर्तगाल यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है और यह आइबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है।
 - ⊕ सीमाएं: इसके उत्तर और पूर्व में स्पेन तथा दक्षिण व पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है।
 - ⊕ इसमें दो स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं: मेडेरा और अज़ोरेस द्वीपसमूह, जो अटलांटिक महासागर में स्थित हैं।
 - ⊕ लिस्बन यूरोप के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
 - ⊕ जलवायु: समुद्री समशीतोष्ण जलवायु; उत्तर में ठंडी और वर्षा वाली, तथा दक्षिण में गर्म एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है।
 - ⊕ भूभाग: टैगस नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, देश को दो भागों में बांटती है; उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में समतल मैदान है।
 - ⊕ सबसे ऊंचा बिंदु: पोंटा डो पिको (पिको या पिको ऑल्टो)

